वेबसाइट लॉन्च कराकर कोरोना कंट्रोल कर रहा फरीदाबाद प्रशासन

साइट के जरिए कोरोना कैसे नियंत्रित होगा, कोई नहीं जानता

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शहर में वेबसाइट लांच कर कोरोना भगाया जा रहा है। आपदा में अफसरों से नजदीकी बढ़ाकर अवसर की तलाश में भटक रहे कुछ स्वयंभू समाजसेवियों ने मीडिया की मदद से इस खेल को रच डाला। वेबसाइट को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने लघु सचिवालय में किया। हालांकि जिस एनजीओ ने इसे लॉन्च किया, उसने ऐसा संकेत दिया कि इसमें फरीदाबाद जिला प्रशासन और जिला रेडक्रॉस पार्टनर है। लेकिन कोविड फरीदाबाद डॉट कॉम नामक इस वेबसाइट पर जाने से पता चलता है कि इसमें जिला प्रशासन और रेडक्रॉस के लोगो (चिन्ह) का सिर्फ इस्तेमाल भर है, बाकी जो सूचनाएं इस साइट पर हैं, वो सभी जगह उपलब्ध हैं और कोई नई बात इसमें नहीं है। अलबत्ता जैसे ही आप इसमें दिया गया फॉर्म भरते हैं तो आपका सारा डेटा एनजीओ के पास चला जाएगा, जो साइबर कानून के तहत अनैतिक है। नियमानुसार वो डेटा जिला प्रशासन तो ले सकता है लेकिन किसी एनजीओ को नहीं मिल सकता।

एनजीओ की असलियत

जिस एनजीओ पहचान ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसे लॉन्च करने का दावा किया है, उसकी असलियत जानिए। 2019 में शुरू हुए पहचान

एनजीओ के फेसबुक पेज से पता चलता है कि मात्र 559 लोग उसके पेज को फॉलो करते हैं। यानी पहचान की सोशल मीडिया उपस्थिति बहुत ही मामूली है और इसकी संचालक के ट्विटर हैंडल को देखने से पता चलता है कि 240 लोग उन्हें वहां फॉलो करते हैं।

यानी फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने अगर ऐसे ही एनजीओ से तालमेल कर कोरोना भगाने का संकल्प लिया है तो उनके साथ सहानुभूति जताने के अलावा क्या किया जा सकता है। जिला प्रशासन को अगर वेबसाइट के जरिए ही कोरोना भगाना था तो किसी नामी-गिरामी एनजीओ से तालमेल कर सकता था। पहचान एनजीओ की एक खबर वाली वेबसाइट भी है जो सिर्फ फरीदाबाद की खबरें देती है। हालांकि उस पर कोई आलोचनात्मक खबर नहीं होती लेकिन पोर्टल को एनजीओ के मुकाबले ज्यादा प्रोफेशनल ढंग से बनाया गया है और उस पर बेहतर कटेंट है लेकिन पहचान एनजीओ से इस पोर्टल का क्या संबंध है, यह रहस्य का विषय है। आमतौर पर बेहतरीन एनजीओ अपनी वेबसाइट का उल्लेख अपने फेसबुक पेज पर करते हैं लेकिन पहचान एनजीओ की कोई वेबसाइट नहीं है। जो कुछ है वो पोर्टल है, जहां एडिटोरियल बोर्ड के पेज पर पहचान एनजीओ की संचालिका ने खुद को उस समाचार पोर्टल का संस्थापक और सीईओ लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत सारे एसोसिएट एडिटर्स हैं। इस तरह यह साफ हुआ कि फरीदाबाद जिला प्रशासन और रेडक्रॉस ने जिस संस्था को अपने साथ जोड़ा है उस संस्था का एक धंधा समाचार पोर्टल का भी है। जाहिर सी बात है कि यह मामला कितना निष्पक्ष है, यह पाठकों के विवेक पर छोड़ा जा रहा है।

कोविड फरीदाबाद डॉट कॉम पर पहचान के अलावा एक और एनजीओ का जिक्र है, जिसका नाम जय सेवा फाउंडेशन है। यह फाउंडेशन किस शहर में है, इसका पता क्या है, इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, यह सारी सूचना आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी। फरीदाबाद के डीसी को अगर इस फाउंडेशन ने प्राइवेट सूचना दे रखी हो तो अलग बात है।

भारत सरकार के एनजीओ नियमों के मुताबिक इस फाउंडेशन को इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति जाहिर करनी चाहिए। अगर जिला प्रशासन ने इसे किसी राजनीतिक दबाव के तहत अपने साथ जोड़ा है तो अलग बात है या हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी डीलर पत्रकार की सिफारिश पर जय सेवा फाउंडेशन को रातोंरात खड़ा कर दिया गया हो और अफसरों से निकटता बढ़ाकर काम निकलवाने का फंडा इसके पीछे हो। अभी शहर में बहुत सारे पोर्टल और एनजीओ इसी तरह कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं जिनका काम है अफसरों से इस बहाने निकटता बढ़ाना और धनकुबेरों पर ऐसा दिखाकर रौब जमाना। इस नेक्सस में काफी लोग शामिल हैं।

नेताओं और अफसर ने क्यों ली दिलचस्पी

17 मई को लघु सचिवालय में इस वेबसाइट की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तो पहुंचे ही, इसके अलावा मंत्री मूलचंद शर्मा, भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रिखा और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी पहुंचे। समझा जाता है कि एक पत्रकार की सिफारिश पर ये सारे लोग लॉन्चिंग समारोह में जा पहुंचे। जिला प्रशासन पर इस वजह से एक तरह से इन सभी का राजनीतिक दबाव भी था। इसलिए वो कोरोना नियंत्रण के नाम पर इसमें पार्टनरशिप करने के लिए राजी हो गया। हालांकि जैसा बताया जा चुका है उस वेबसाइट पर दी गई सारी सूचनाएं खुद जिला प्रशासन ने समय-समय पर मुहैया करा रखी हैं।

इसके अलावा अन्य वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं, ऐसे में फरीदाबाद में कोरोना नियंत्रण इस वेबसाइट से कैसे होगा, यह इसके संचालक ही बता सकते हैं। इतना तो साफ है कि शहर में नेताओं, अफसरों और प्रॉपर्टी डीलरों, पत्रकारों से मिलकर कुछ लोग समाजसेवा का ढोंग कर रहे हैं और इसकी आड़ में धंधा कर रहे हैं।

करनाल का मोर्चा

इन्द्री में भाजपा नेताओं की दुकानें खुलीं तो बाकी ने भी खोल लीं

इंद्री, (जेके शर्मा) सरकार ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाकर शर्तों की पालना के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन इन नियमों को ठेंगा दिखाने में भाजपा के नेता सबसे आगे खड़े हो गए। इंद्री शहर में नियमों की परवाह न करते हुए भाजपा के नेता सरेआम दुकान खोल कर लोगों को सामान दे रहे है। उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन भी लगी हुई है। जब उन्हें दूसरे दुकानदार दुकान न खोलने के लिए कहते है तो वह लोगों को कह रहे हैं कि सरकार में उनकी खूब चलती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना ही नहीं विधायक हमारे इशारे पर चलते है।

विधायक के इन चहेतों के देखादेखी दूसरे दुकानदार भी अपनी दुकानें खोलकर भीड़ बढ़ा रहे है। दूसरे लोग भी नियमों को तोड़कर बाजार में दुकानें खोल कर कहते है कि जब भाजपा वालों को कोई नहीं रोकता तो फिर कानून क्या केवल हमारे लिए ही है। भीड़ की वजह से दोपहर पहले तो बाजार में हालात बहुत ही डरावने हो रहे हैं। इन्द्री में प्रशासन की अंधेरगर्दी के कारण लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों की संख्या बढ़ रही है।

हालात तो तब खराब हो जाती है जब सत्तासीन पार्टी के नेता ही लॉकडाउन को ठेंगा दिखाने लग जाते हैं। ऐसे में अन्य लोगों

पर बुरा असर पड़ता है। लोगों में भाजपा नेताओं के कारनामों की चर्चाओं से मनोहर लाल की सरकार बदनाम हो रही है। क्या सत्ता में बैठे नेता ओर के लिए नसीहत और खुद मियां फजीहत के मुहारे को चिरतार्थ कर रहे हैं।

हरियाणा में भाजपा के लिए अलग कानून और आम आदमी के लिए आम कानून है क्या? जब इस बारे में इंद्री थाना प्रभारी सतपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बाजार में नियमित रूप से नियमों की पालना कराने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, जो भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करते उनके के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नियमों की उलंघना की इज्जात नहीं है।

'आप' जैसा करके दिखाएं बाकी राज्य : अनिल वर्मा

इन्द्री, (जेके शर्मा) आम आदमी पार्टी के संयोजक अनिल वर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना के दौरान जनहितैषी काम किए हैं, उसी तरह हरियाणा समेत बाकी राज्य भी काम करके क्यों नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार करीब 72 लाख कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में राशन देने, कोरोना से मौत होने पर पीड़ितों के परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। जिस परिवार में कमाने वाला नहीं है। और जो बच्चे अनाथ हुए उन बच्चों को 25 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा एवं 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने की है। इस घोषणा से दिल्ली की जनता में खुशी की लहर है। अनिल वर्मा ने खट्टर सरकार की कड़ी आलोचना की है।

जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन, कई मुकदमे निपटे

करनाल, (ममो): मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, करनाल जसबीर ने जिला कारागार, करनाल में मंगलवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया। छोटे अपराधों में शामिल 8 अपराधों जैसे घोषित अपराधी, चोरी आदि को सीजेएम के समक्ष लाया गया। जिनमें से 5 मुकदमों को मौके पर निपटाया गया और जिनमें संलिप्त 6 विचाराधीन कैदियों को कबूलनामे के आधार पर कि वे भविष्य में ऐसे अपराध नहीं करेंगे, को अंडरगॉन किया गया। सीजेएम ने जेल अधीक्षक को उन मामलों की छानबीन करने का भी निर्देश दिया, जहां छोटे-छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदी हैं ताकि ऐसे मामलों में अगले महीने होने वाली जेल लोक अदालत में इन विचाराधीन कैदियों के मामलों को रखा जाए। उन्होंने जेल परिसर और कैदियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। विचाराधीन / अंडर-ट्रायल कैदियों का साक्षात्कार लिया गया और किसी भी दोषी या अंडरट्रायल कैदी ने ब्रेक-फास्ट, लंच या डिनर आदि के समय या अन्य जीवित स्थितियों के संबंध में उन्हें भोजन की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में कोई शिकायत नहीं की तथा जेल परिसर को स्वच्छ पाया गया।

यूपी की तर्ज पर रोडवेज कर्मियों ने मांगी 50 लाख की मदद

करनाल, (जेके शर्मा) ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार से हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों को कोरोनाग्रस्त होने पर मदद देने की मांग की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा और महासचिव सुखविंदर बयाना ने कहा कि हरियाणा सरकार करोना काल में यात्रियों की सेवा में रोडवेज चालक-परिचालकों का संपर्क आम लोगों से अधिक होने के कारण उनके करोनाग्रस्त होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसी के चलते हरियाणा में 100 से अधिक कर्मचारी करोनाग्रस्त हो चुके हैं तथा दर्जन से अधिक कर्मचारियों की करोना के कारण मौत हो चुकी है। करोना महामारी के चलते उपजे हालात की वजह से रोडवेज कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पनप रही है। ऐसे में सरकार को रोडवेज कर्मचारियों का ना केवल उत्साहवर्धन करना चाहिए, बल्कि उनकी परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

रोडवेज वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को करोना योद्धा मानकर करोना की वजह से मौत होने पर उन्हें 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय की यूनियन सराहना करती है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हरियाणा में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने महकमे के कर्मचारियों के करोना से बचने तथा उनका उत्साहवर्धन करने की योजना तैयार की है। इस तरह की योजना से कर्मचारियों का काम के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। इसीलिए रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी विभाग विशेष योजना तैयार करें।

कर्मचारी नेताओं ने रोडवेज के सभी डिपो व सब डिपो पर कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने और उनके करोना से संबंधित जांच कराने सहित दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की मांग की। रोडवेज चालक-परिचालकों के लिए मास्क व सेनिटाइजर सहित अन्य सुविधाएं देने की पूरी व्यवस्था कराई जाए।

नगर निगम को फोन कर पेड़ों की छंटाई करवाएं

करनाल, (ममो): सड़कों पर खड़े पेड़ों की ऊंची व घनी टहनियां अब ट्रैफिक और बिजली की तारों को बाधित नहीं करेंगी। नगर निगम आयुक्त विक्रम ने बताया कि पेड़ों को छंटाई करने वाली मशीन को ठीक करवा लिया गया है और अब उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कार्यकारी अभियंता बागवानी नरेश त्यागी को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी मॉनसून सीजन से पहले-पहले पूरे शहर का सर्वे कर सड़क किनारे फैले पेड़ों की आवांछित शाखाओं की छंटाई करवा दें, ताकि तेज हवा व बारिश के दौरान इनके गिरने से होने वाले हादसे को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इस मशीन में कुछ तकनीकि खामी आ गई थी, जिसे अब दुरूस्त करवा लिया गया है और वह अपना काम सुचारू रूप से कर रही है।

निगमायुक्त ने बताया कि पेड़ों की छंटाई के लिए निगम की बागवानी शाखा के कर्मचारी शहर में जाएंगे और पार्षदों व नागरिकों की ओर से जहां-जहां से भी शिकायत आएगी, सम्बंधित क्षेत्र के वृक्षों की छंटाई करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नागरिक इसके लिए निगम के टोल फ्री नम्बर 1800 180 2700 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त पार्क किनारे फैले पेड़ों की ट्रिमिंग भी की जाए, इससे पार्कों की सुदंरता में भी इजाफा होगा।